POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–6 JUNE 2024 AMBERNATH PAGE 1 OF 4 RS 5/-

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा मीडिया का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना , प्रारंभ मे एक मासिक के रूप में शुरू, इस मासिक समाचार पत्र का मूल उद्देश्य है । पाठक अपना विचार हिन्दी या अंग्रेजी में बेहिचक दे सकते हैं । शर्त सिर्फ यह है कि विचार किसी भी तरह के , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए ।

email id: vote1957@gmail.com

अंतराष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल से फिलिस्तीन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई रोकने का आदेश दिया

दक्षिण अफ्रीका द्वारा याचिका की सुनवाई के बाद तथा फिलिस्तीन के गाजा तथा रफाह में मानवीय संकट के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। आदेश निम्न है:-

1. सैनिक कार्रवाई तुरंत बंद हो।
2. मानवीय सहायता सामग्री के आने जाने के लिए रफाह क्रॉसिंग खुला रखें।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अधिकृत जांच आयोग, मिशन का अबाधित आना जाना सुनिश्चित हो।

देखने की बात होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसे वैश्विक निकायों के आदेश कितने प्रभाकारी होते हैं !

Mamata Defying High Court Order Is Not Only Unwarranted But Contemptuous As Well

The way Mamata Bannerjee , CM, West Bengal reacted histrionically in defiance of the Calcutta High Court Order Cancelling the OBC Certificates invalidating the norms prepared for determining the OBC.

There is scope for appeal to Supreme Court. If she finds fault with the High Court order - she can very well approach the Supreme Court instead of reacting wildly to the judiciary.

The behaviour puts her in a very bad stead. Moreover she can be proceeded with the contempt of court proceedings as well.

ये कैसा न्याय है, भाई !

महाराष्ट्र के पुणे में अमीर बाप के एक नाबालिग लाड़ले ने दारू के नशे में करोड़ों रुपए की पोर्शे कार से बाइक सवार दो युवा इंजीनियरों को रौंद कर, कुचल कर मार डाला और माननीय न्यायालय ने तथाकथित नाबालिग आरोपी को पुचकारते हुए 300 शब्दों में दुर्घटना पर एक निबंध लिखने की हिदायत देते हुए बड़े आराम से जमानत दे दी।जजों को भी प्रशिक्षण देने की सख्त जरूरत है।

उबाऊ चुनाव

भारत में अबतक का सबसे लंबा करीब ढाई महीनों तक चलने वाले सात चरणों वाले चुनाव का प्रचार आज समाप्त हो रहा है। भयंकर गर्मी में भाषण देने वाले नेता तथा भाषण सुनने वाले श्रोता तथा इनकी सभाओं में भाग लेने वाले इनके कार्यकर्ताओं के लिए सचमुच राहत की बात है।

नेता तथा श्रोता ढाई महीने से एक ही बात बार बार बोल बोल कर तथा सुन सुन कर स्पष्ट रूप से ऊब गए होंगे।

तिस पर चुनावी भाषणों का गिरता स्तर जिसमें नेता एक दूसरे के खिलाफ निजी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आते हैं।धर्म का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाषणों में प्रयोग करना , चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की बातों पर सख्ती से पेश नहीं आना इस ऊब को और बढ़ा देता है।

क्या इतने सारे चरणों में चुनाव कराना उचित हैं ?जबकि कानूनी रूप से इसमें कुछ भी गलत नहीं है फिर भी लोगों में चुनावों के प्रति अन्यमनस्कता जरूर पैदा होने लगती है।एक बैलट पेपर का जमाना था जब कि वोट डालने का काम एक ही दिन में सारे भारत में पूरा हो जाता था तथा गिनती भी चुनाव के ठीक दूसरे दिन शुरू हो जाती थी।पर आज सारी सुविधाएं हैं पर चुनाव कराने में चुनाव आयोग को ढाई महीने लगते हैं !

A Former High Court Judge Stooping So Low !

Election Commission of India has rightly debarred Abhijit Gangopadhyay ,the former Judge of Calcutta High Court from campaigning for his election for 24 hours. The ECI should have debarred him for the remaining period for the election campaigning given the vulgar language used by him for Mamata Bannerji the Chief Minister of West Bengal. The ex -judge is a BJP's candidate for MP from Tamluk constituency in WB.

He said on May 15 while addressing an election rally:-

"Mamata Banerjee, how much are you being sold for? Your rate is Rs10 lakh, why? Because you're getting your make-up done by Keya Seth? Mamata Banerjee, is she even a woman? I keep wondering sometimes".

Such language emanating from a High Court judge is really disgusting and this gives me reason to doubt our collegium system which appoints such judges of superior courts !

Deaths Due To Accidents In India

Series of mishaps taking place in matter of few days (like the hoarding mishap in Ghatkopar, Mumbai taking 17 lives, boiler blast in Dombivali near Mumbai taking 11 lives, Porshe Car accident in Pune taking lives of two youthful engineers, massive fire in the gaming zone in Rakot , Gujarat taking 33 lives, a fire in a Baby Care Center in Delhi taking lives of 7 newborn children) has pronpted me to highlight the accidental deaths running into lakhs taking place in India every year with no serious concern visible in our society as if people have got used to such things

As per NCRB (National Crime Records Bureau) of Government Of India 430504 deaths took place due to accidents in India in the year 2022 . It works out to 1180 deaths per day on an average. Should we not be concerned of such deplorable situations , more so, when we keep talking of becoming World Leader or Vishwa Guru in coming years !

Now let us see just the top ten States and Cities which account for the highest occurrence of deaths which could probably be prevented if the Govts really feel themselves concerned with :-

SN	State	Death	City	Death
1	MH	66656	Mumbai	8510
2	MP	43726	Pune	4821
3	UP	42930	Bengaluru	4137
4	TN	29115	Delhi	3571
5	KTK	29090	Jaipur	2516
6	Raj	26449	Surat	2232
7	Guj	22410	Kanpur	2198
8	Odisha	21013	Nagpur	2192
9	CG	16893	Ahmedabad	2021
10	Haryana	16041	Faridabad	1438

Routine and sincere attention to structural audits and other compliances could go a long way in preventing such accidents and saving precious lives if not properties.

बहुत देर कर दी, हुजूर, आते आते !

अब जबकि लोकसभा चुनाव लगभग समाप्त होने को है - अन्ततः चुनाव आयोग ने आंख खोली तथा प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों में सांप्रदायिक बातें होने की शिकायतों का दखल लेते हुए , दिखावे के लिए ही सही, कुछ कार्रवाई तो की !

सामान्यतः चुनाव आयोग आदर्श आचरण संहिता की अवहेलना करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देता है तथा चेतावनी भी। पर इन सर्वोच्च नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग ने नया तरीका इजाद किया है। नोटिस उम्मीदवार की पार्टी के अध्यक्ष को दिया गया है प्यार से आग्रह करते हुए कि नेताओं द्वारा संहिता का उल्लंघन ना होने दें।

चुनाव आयोग ने कांग्रेस के अध्यक्ष को भी नोटिस दिया है कि वे अपने नेताओं पर नियंत्रण रखें। उनका कहना है कि ये लोग बार बार संविधान खतरे में है कहते फिरते हैं।जबकि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रचार पर बंदी लगा कर या अन्य तरह से।

चुनाव आयोग बूथों पर हुए वोटिंग का आंकड़ा अपने वेब साइट पर अपलोड करने में आनाकानी कर रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर कहा है कि फॉर्म 17C वेबसाइट पर अपलोड करना बहुत सारी समस्याओं को निमंत्रण देना होगा। ये तर्क समझ के परे है। डाले गए मतों का विवरण वेबसाइट पर डालने में क्या हर्ज है।

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–6 JUNE 2024 AMBERNATH PAGE 2 OF 4 RS 5/-

असमान से गिरा , खजूर में अटका

केजरीवाल जेल से छूटे तो मालीवाल प्रकरण में अटक या अटका गए लगते हैं।

स्वाति मालीवाल के मामले में कुछ विशिष्ट बातें निम्न हैं:-

1. गोदी मीडियाकर्मी का सहयोग उत्साहवर्धक है। ऐसा उत्साह मणिपुर तथा बृज भूषण शरण सिंह के मामले में एकदम गायब था !

2. इस मामले में बीजेपी के नेता समर्थक बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं मालीवाल के समर्थन में जबकि मणिपुर (महिलाओं का नंगा परेड कराए जाने वाली घटना) तथा बृज भूषण शरण (महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी) मामले में एकदम शांत थे।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग ने अतिशीघ्र दखल किया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में भी तत्परता दिखाई। पर ये बात और है कि अब शिकायत हो रही है कि संदेशखाली मामलों में पीडितों से झूठी शिकायत कराई गई है।

4. दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी भी काबिले तारीफ है। महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था तब इसी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था।

5. अभियुक्त तथा पीड़ित दोनों ही एक ही पार्टी - आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं।

6. दुर्व्यवहार या मारपीट हाल ही में चंद दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर छूटे तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के अंदर हुई है। खुद के आवास के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले या तो मूर्ख हो सकते हैं या सचमुच शातिर।

7. इस घटना को अंजाम देने के पीछे इरादा या नीयत (motive) का अबतक पता नहीं चला है।

8. समाचारों के मुताबिक स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी। इसका मतलब है कि उन्होंने इसके लिए अपॉइंटमेंट तो लिया होगा ! अगर अपॉइंटमेंट है तो सिक्योरिटी कर्मियों के साथ इतना नॉकझोंक क्यों ! सिक्योरिटी की बात मानकर उन्हें वापस चले जाना चाहिए था।

9. सीसीटीवी से अच्छादित मुख्यमंत्री के अधिकृत आवास के स्थान पर मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ का दुर्व्यवहार समझ से परे है।

10. अग्रिम जमानत की अर्जी के सुनवाई पूरी होने के पहले ही केजरीवाल के पीए की गिरफ्तारी समझ से परे है। ऐसा अग्रिम जमानत अर्जी को निष्प्रभावी बनाने के लिए भी किया गया होगा। ज्ञातव्य है कि सीएम के पीए ने संबंधित पुलिस थाने में अर्जी दी थी कि वे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मतलब अभियुक्त के फरार होने की संभावना नहीं थी।

11. मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 5 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दे देना। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए तथा शीघ्र मिलनी चाहिए।

पर इस सरकार का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि गिरफ्तारियां फुर्ती से कर ली जाती हैं। मुकदमे की सुनवाई (trial) में जानबूझ कर देर की जाती है। बाद में अभियुक्त या तो जमानत पर छोड़ दिए जाते हैं या सुनवाई के बाद बरी हो जाते हैं। भीमा कोरेगांव मामले में ऐसा हो रहा है। सीएए के खिलाफ आंदोलनकारियों के साथ ऐसा हुआ है। तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ऐसा हुआ है।

एक गलत विधिशास्त्र (jurisprudence) -"प्रक्रिया ही दंड है" का भरपूर लाभ लेती है ये सरकार ।

बाइडेन - ट्रंप बहस के लिए तैयार

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा पूर्व राष्ट्रपति तथा विपक्ष के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने आपस मे खुले बहस (Public debate) की तत्परता दिखाई है। >>>>>

Kapil Sibal Won The Contest

Congratulations to Senior Advocate Kapil Sibal who has been elected to the post of President of the Supreme Court Bar Association (SCBA) !

Kapil Sibal secured 1066 votes, while the next contender Senior Advocate Pradeep Rai got 689 votes. The incumbent President Senior Advocate Dr Adish C Aggarwala secured 296 votes (the figures are tentative).

Recently the conduct of the incumbent now outgoing President of the SCBA Dr Adish Aggarwal has brought in disrepute and controversy in this coveted organisation of advocates of the Supreme Court. Dr Adish Aggarwal had written a letter to President of India and also intervened in the Supreme Court against the disclosure of identities of the donors and donees of the Electoral Bonds Scheme which has been set aside being unconstitutional.

Advocates can have inclination to different ideologies but when it comes to laws they should always be seen taking side of law irrespective of their ideologies.

As such the advent of Kapil Sibal to the SCBA is very much reassuring to people for whom rule of law matters.

सूरत के सांसद का निर्विरोध चुनाव अभूतपूर्व

गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने सचमुच इतिहास बनाया है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि भारत के संसद के इतिहास में या यहां तक कि विधान सभाओं के चुनावों में ऐसा कभी भी हुआ है। हां, स्थानीय चुनावों में ऐसा होना आश्चर्य नहीं माना जाता क्योंकि इनका दायरा बहुत छोटा होता है जहां प्रभाव चल सकते हैं।

सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज होना, इसी पार्टी द्वारा वैकल्पिक प्रत्याशी का नामांकन का भी खारिज होना, बीएसपी तथा स्वतंत्र सभी प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन वापस लेना किसी भी निष्पक्ष समीक्षक के मन में शंका या आश्चर्य तो जरूर पैदा करता है।

मुझे पता नहीं है कि नामांकन किस आधार पर रद्द किए गए। पर मामूली तकनीकी औपचारिकताओं के अभाव में किसी का भी नामांकन रद्द करना उचित नहीं है।इसी तरह से सभी अन्य प्रत्याशियों द्वारा अपना अपना नामांकन वापस लिया जाना भी शंका तथा आश्चर्य जरूर पैदा करता है।

आश्चर्य इस बात का और है कि किसी भी संबंधित या प्रभावित पक्ष या व्यक्ति द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत नहीं सुनी गई है।फिर भी मेरा मानना है कि लोकतंत्र के हित में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने से क्या बचा जा सकता था ! जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि अन्य प्रत्याशियों ने क्या सचमुच अपनी स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया है और अगर हां तो अचानक हृदय परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं !वरना इस तरह की रवैया जारी रही तो भविष्य में सारे चुनाव निर्विरोध हो जायेंगे तथा चुनाव के भारी खर्च तथा सारी तकलीफों से निजात मिल जायेगी।जांच एजेंसियों के डर से लोग दल बदल सकते हैं तो नामांकन वापस लेना कौन सी बड़ी बात हो सकती है !

काश भारत में भी ऐसा होता !हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जस्टिस मदन बी लोकुर , दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जज ए पी शाह तथा द हिंदू के पूर्व प्रधान संपादक एन राम ने इस तरह की बहस की पेशकश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिख कर।

राहुल गांधी ने तो स्वीकृति में जवाब भी दिया था। पर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई उत्सुकता नजा र नही आई।

लोकतंत्र में ऐसी बहस होती रहनी चाहिए !

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–6 JUNE 2024 AMBERNATH PAGE 3 OF 4 RS 5/-

न्यूज क्लिक के संस्थापक तथा संपादक प्रबीर पुरकायस्था को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

3 अक्टूबर 2023 से यानी करीब 8 महीने से जेल में बंद एक बुद्धिजीवी को अंतत: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी तथा पुलिस रिमांड लेने के तौर तरीकों पर सवाल उठाया है।

ज्ञातव्य है कि

1. 3 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्था के न्यूज क्लिक के दफ्तरों में पुलिस का छापा

2. 3 अक्टूबर को उन्हें पुलिस के घेरे में रखा गया उनकी गिरफ्तारी का कारण बताए बगैर।

3. 4 अक्टूबर को सुबह तड़के 6 बजे के पहले दिल्ली के एडिशनल सेशन जज के घर पर ले जाया गया पुलिस कस्टडी के रिमांड के लिए बिना पुरकायस्था या इनके वकील को खबर दिए।

4. 4 अक्टूबर को ही तड़के 6 बजे जज साहब रिमांड पर भेज देते हैं।

5. तब से अब तक वयोवृद्ध पत्रकार को जेल की हवा खिलाई जा रही है।

6. सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गिरफ्तारी का कारण नहीं बताए जाने की कमी को संविधान के आर्टिकल 21 तथा 22 का उल्लंघन मानते हुए इनको जमानत पर छोड़ने ड का आदेश दिया है आज !

जजों की टिप्पणी साबित करती हैं कि किस तरह से सरकार के विरोधियों को जेल में अकारण रखा जा रहा है।

1.जजों ने जानना चाहा कि सुबह छह बजे रिमांड लेने की अर्जेंसी क्या थी ?

2. अभियुक्त को रिमांड एप्लीकेशन की जानकारी क्यों नहीं दी गई ताकि वे रिमांड एप्लीकेशन का विरोध कर सकते थे

4 जून के बाद केंद्र सरकार किसकी बनेगी !

सामान्य (Thumb Rule) अनुमान

इसमें कोई शक नहीं है कि आज बीजेपी पहले की कांग्रेस की जगह ले चुकी है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही रहेगी।

मुझे लगता है कि सरकार बनाने में कुछ मुश्किल जरूर आ सकती है पर हेराफेरी कर के सरकार भी बना लेगी।

बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक , पश्चिम बंगाल में अगर 50:50 भी कर लें तो बीजेपी 303 से बहुत नीचे या 273 से भी नीचे आ सकती है।

इन चारों राज्यों में कुल 40+48+28+42 = 158 हैं।अगर इसका आधा (79) भी इंडिया एलायंस को आ गया मतलब आधा (79) बीजेपी का कम हो गया तो बीजेपी 303 - 79 = 224 पर सिमट जाएगी।

अगर इन कुल सीटों का एक चौथाई यानी 40 सीट भी कम होता है तो बीजेपी 303 - 40 = 263 पर आ जायेगी । मतलब बेंचमार्क से 10 सीट कम रहेगी।

इसमें उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी का सीट थोड़ा थोड़ा भी कम हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है।

अगर इंडिया एलायंस के पोस्ट पोल एलायंस को बहुमत आता है तो प्रधानमंत्री के पद के लिए रस्सा खींच हो सकती है पर ज्यादा सीट वाली पार्टी के सिद्धांत पर कांग्रेस का हक रहेगा तथा समझौता भी हो सकती है !

गौतम नौलखा की जमानत पर से रोक हटी !

भीमा कोरेगांव मामले में आज चार साल से जेलबंद (जिसमें कुछ समय हाउस अरेस्ट का भी है) गौतम नौलखा को छह महीने पहले मुंबई हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया इस टिप्पणी के साथ कि इनके ट्रायल में पता नहीं और कितने साल लगेंगे । दस साल से कम किसी भी हाल में नहीं लगेगा।

ज्ञातव्य है कि पिछले दिसंबर में मुंबई हाई कोर्ट ने इन्हे जमानत देते हुए टिप्पणी की थी कि इनके खिलाफ kli मामला ही नहीं बनता है। कोई सबूत नहीं। हाईकोर्ट ने एनआईए कोतीन हफ्ते दिए अपील के लिए जिसके दौरान एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था तथा मुंबई हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर आयात अंतरिम रोक को जारी रखने से मना कर दिया ।

भीमा कोरेगांव मामले में कुल गिरफ्तार बुद्धिजीवियों ने से अबतक 6 या सात लोग जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। फादर स्टेन स्वामी की जान चली जेल में ही। उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई होती ही रह गई थी।

सेक्स रैकेट में उलझे प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भागे*

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा जेडीएस नेता एच डी देवेगौड़ा के पोता तथा कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीएस के नेता तथा लोकसभा एमपी प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर सैकड़ों लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप है, राजनयिक पासपोर्ट पर विदेश (जर्मनी) भागने में सफल रहे तथा किसी को पता तक नहीं चला। ठीक उसी तरह जिस तरह से कुछ वर्ष पहले नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के हजारों करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए।

पहले की तरह अब भी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को दोष देंगे कि तुम्हारी गलती से भागे !

पर भारत सरकार ऐसे लोगों को जारी राजनयिक पासपोर्ट तो रद्द कर सकती है ताकि ऐसे लोगों को विदेश से भारत में लाकर कानून के हवाले करना आसान हो ।

पर क्या भारत सरकार ऐसा करेगी !

महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बृज भूषण शरण सिंह का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केंद्र सरकार का सहयोग स्पष्ट दिखता है कि बीजेपी ने उनके बेटे को लोकसभा से चुनाव लड़ने का टिकट दिया है।

इसी तरह जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन है कर्नाटक में। ऐसे में इस आरोपी को भारत में लाकर न्याय के हवाले करने में कितनी सफलता मिलेगी यह देखने की बात रहेगी

बिहार ने अपना एक सच्चा नेता खो दिया

सुशील कुमार मोदी एक शांत, सौम्य तथा जानकार राजनेता थे। उन्हें मैने कभी उत्तेजित होकर वक्तव्य देते नहीं देखा। मुझे उनकी बराबरी का बिहार की राजनीति में कोई बुद्धिजीवी नहीं दिखता है।

उनका स्वभाव आज के बीजेपी के नेताओं से बिलकुल अलग था।

नीतीश कुमार तथा सुशील कुमार मोदी की दोस्ती खूब चली ! बिहार में पिछली बार जब सरकार बनी थी उस सरकार में वे नीतीश कुमार के साथ नहीं रह पाए क्योंकि बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय स्तर पर उनकी सेवा लेना उचित समझा।

मेरी समझ से सुशील कुमार मोदी बात से ज्यादा काम पर ध्यान देते थे। बिहार के अन्य नेताओं को उनकी कार्यपद्धति से सीख लेनी चाहिए।

ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–6 JUNE 2024 AMBERNATH PAGE 4 OF 4 RS 5/-

Miscellaneous

Narendra Modi PM India

कांग्रेस ने देश की सेना की जरूरतों को भी अपनी अवैध कमाई का जरिया बना दिया, वहीं मोदी आज हमारी सेनाओं को अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है।

Sitaram Yechury , GS, CPIM , tweets

विनाश काले विपरीत बुद्धि! It's shocking to hear PM Modi's claim that the world only learned about Mahatma Gandhi after the 1982 film 'Gandhi'. Father of the Nation, Gandhi never needed anybody to promote his unparalleled legacy as a symbol of peace and non-violence! Before Modi was born Gandhi was nominated 5 times for the Nobel Peace prize! He was never awarded as India was a colony under Pax Brittanica!

Prashant Bhushan , Senior Advocate tweets

30 तारीख़ को चुनाव प्रचार ख़त्म होने के बाद शुरू होगा मोदी का आख़िरी चुनावी दाँव! कन्याकुमारी के विवेकानन्द रॉक पर ध्यान करेंगे। सिर्फ़ कैमरे होंगे! 2 हज़ार का सैनिक बल उनकी रक्षा करेगा और पूरे एरिया को लोगों से ख़ाली कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि वह ध्यान झोला उठाने के बाद क्या करेंगे उस पर होगा या कैसे तोड़फोड़ करके नई सरकार बनाएंगे उस पर होगा?

Sudheendra Kulkarni, former Director of Operation PMO, tweets

Four years in jail — without bail or trial. Is this justice? Is it fair? Commence and complete the trial, and then give Umar Khalid the sternest punishment under the law if he's found guilty. But why punish without trial?

I want my country, the land of Buddha, Mahavir, Nanak and Mahatma Gandhi, to condemn Israel's genocidal killing of innocent Palestinians in the strongest possible words.

Tejashwi Yadav , Former Bihar Deputy CM and RJD leader tweets

प्रधानमंत्री हार के डर से अब चुनावी सभाओं में मुझे जेल भेजने की तारीख बता रहे है। प्रधानमंत्री की यह सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है कि वे जाँच एजेंसियों को अपना खिलौना समझते हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार विपक्ष के किसी भी नेता को मनगढ़ंत एवं काल्पनिक केस में जेल भेज सकते है? क्या प्रधानमंत्री इसलिए ही संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो मेरे कोरे झूठ का विरोध करेगा, जो मेरी विफलताओं का पर्दाफ़ाश करेगा उसे सीधा जेल में डाल देंगे? क्या संविधान समाप्त करने की प्रधानमंत्री की यह सीधी स्वीकारोक्ति नहीं है?

Arvind Kejriwal, CM Delhi tweets

मोदी जी का अहंकार अब इतना बढ़ गया है कि वो ख़ुद को भगवान का अवतार बता रहे हैं। मैं RSS से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो भी मोदी जी को भगवान मानते हैं? RSS को देश को इस सवाल का जवाब देना होगा।

Kapil Sibal , President, Supreme Court Bar Association

Modi : On Tejasvi Another guarantee to the people of Bihar : "…Once he completes his rounds on the helicopter, his road to jail will be decided" My take : 1)Violation of MCC 2)Confession that agencies act on his bidding 3)ECI will not act 4)No nation deserves this.

Prashant Kishore , Electiom Analyst tweets

देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में एक विश्वसनीय चेहरा @ YogendraYadavजी ने 2024 Lok Sabha elections का अपना "फ़ाइनल आकलन" साझा किया है। योगेन्द्र जी के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी को 240-260 और एनडीए की साथी दलों को 35-45 सीटें मिल सकती हैं। मतलब BJP / NDA को 275-305 सीटें। देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और outgoing Lok Sabha में BJP / NDA की 303/323 सीटें हैं। (Shiv Sena won 18 seats as part of NDA but is no longer with them) अब ख़ुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही हैं। बाक़ी 4 June को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है।

Yogi Adityanath, CM, UP tweets

जो बोले सो निहाल! सत् श्री अकाल! पंजाब की जनता रामद्रोहियों एवं राष्ट्रद्रोहियों को सबक सिखाएगी और हर बूथ पर कमल खिलाएगी। इस उत्साह और समर्थन के लिए आभार आनंदपुर साहिब लोक सभा क्षेत्र वासियो!

Ashutosh, ournalist tweets

जो गांधी को नहीं जानते वो ही गांधी के बारे में ऐसी बात कह सकते हैं ।

Satya Hindi tweets

फ़िल्म ही नहीं मोदी के पैदा होने से पहले विश्वप्रसिद्ध हो चुके थे गाँधी!

Narendra Modi PM, India tweets

कट्टर भ्रष्टाचारियों की पार्टी भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की कोख से ही पैदा हुई है, इसलिए पंजाब के मेरे भाई-बहनों को दोनों से बहुत सावधान रहना है।

Rahul Gandi, Leader Congress Party

आज प्रचार के आखिरी दिन मैं देश की महान जनता को प्रणाम करते हुए कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि INDIA की सरकार बनने जा रही है। मैं गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं जो देश के संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके खड़े रहे। हम जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे और प्रधानमंत्री के बार बार भटकाने के प्रयास के बावजूद किसानों, मज़दूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की आवाज़ उठाई। हम ने मिलकर वैकल्पिक विज़न के रूप में हर वर्ग का जीवन बदलने वाली क्रांतिकारी गारंटियां देश के सामने रखीं और अपना संदेश कोने कोने तक पहुंचाया। मैं आप सभी से अपीलकरता हूं कि अंतिम समय तक पोलिंग बूथ्स और स्ट्रांग रूम्स पर नज़र जमाए रखें।

Printed, published and owned by Harishankar Upadhyay and printed and published at Flat 15B, Jeevan Jyot, Bhidewadi, Kansai Section, Ambernath (East), Dist Thane (Maharashtra), PIN 421501. Editor Harishankar Upadhyay, Mobile 9869435995